THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will allow you after Zero Hour. ...(*Interruptions*)... You can associate.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the Minister should reply.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Sir, I have noted what the hon. Member has stated. I will take the details from here and I will surely enquire into the matter as to why she was not admitted to the hospital.

Reduction in the period of Shri Amarnath Yatra

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): धन्यवाद, सर।

सर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसका जीता-जागता उदाहरण अमरनाथ यात्रा है, जिसमें हर साल देश के कोने-कोने से लाखों लोग जाते हैं। यात्रा जुन में शुरू होती है और अगस्त में राखी तक चलती है। वहां जाने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ती रहती है। आज जब हम religious tourism की बात करते हैं, तो अमरनाथ यात्रा देश में religious tourism का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जम्मू-कशमीर के लोग इस यात्रा के कारण करोड़ों रुपये कमाते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रियों और वहां पर लंगर वगैरह लगाने वाले लोगों के प्रति वहां की सरकार का एटीट्यूड कुछ पॉज़िटिव नहीं है।

कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर में इसी को लेकर एक बहुत बड़ा जन आन्दोलन भी हुआ था, क्योंकि इस यात्रा को लेकर तरह-तरह की अड़चनें डाली जाती हैं, जैसे यात्रा का समय कम करना, यात्रियों की सुख-सुविधाओं को लेकर समस्या पैदा करना या लंगर लगाने पर समस्या पैदा करना। जम्मू-कश्मीर में इसके लिए बहुत बड़ा जन-आन्दोलन हुआ था, जिससे लाखों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई थी।

मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस यात्रा के साथ करोडों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आज इस यात्रा के समय में फिर से कटौती की जा रही है साथ ही ऐसे कानून और रूल्स बनाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों की संख्या कम हो, उनको मिलने वाली सुविधाएं कम हों।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद तीन बार अमरनाथ जी के दर्शन करने गया हूं। इस यात्रा के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अगर सरकार एक समुदाय के सेंटिमेंट्स से खेलते हुए, इस यात्रा के ऊपर तरह-तरह के प्रतिबन्द लगाएगी, यात्रा के समय को कम करेगी, तो इससे देश के लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। मैं आपके माध्यम से वहां की सरकार से निवेदन करता हूं कि आप यह यात्रा शान्तिपूर्वक चलने दें। क्या वे इस यात्रा के समय में तबदीली केवल इसलिए करेंगे, क्योंकि टेररिस्ट कुछ बातें कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या टेररिस्ट इस बात को डिफाइन करेंगे कि यह यात्रा कैसे चलनी चाहिए? वहां पर क्या फेसिलिटी मिले, क्या नहीं मिले, क्या यह चीज़ अब टेररिस्ट डिफाइन करेंगे? कौन से समय पर यात्रा हो, क्या यह अब टेररिस्ट डिसाइड करेंगे?

[श्री अविनाश राय खन्ना]

सर, इस यात्रा में समय का अपना एक अलग महत्व है। मैं चाहूंगा कि सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह यात्रा निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो और जितना समय यह यात्रा चलती है, उतना समय यह चले, रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो और जो संस्थाएं वहां मुफ्त खाना बांटती हैं, लंगर लगाती हैं, उनको भी कोई असुविध न हो। क्या इसके लिए हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ बातचीत करेगी?

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): सर, जो मैटर माननीय सरस्य के द्वारा उठाया गया है, मैं उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा (हिमाचल प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): सर, हम स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Devender Goud.

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha): Would you please come up and speak? (*Interruptions*) आतंकवादियों के लिए तो सरकार खुद खड़ी हो गई है ...(व्यवधान).. दूसरी यात्राओं के लिए तो सरकार खुद खड़ी हो गई है ...(व्यवधान)... immediaely you come and take them away. (*Interruption)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please.. (*Interruptions*) बलबीर पुंज जी, आप बैठिए ...(व्यवधान) आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, ये unilaterally फैसला करते हैं।

श्री तरुण विजय (उत्तराखण्ड): सरकार आतंकादियों के लिए बोलती है ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All of you are speaking at once. What is the problem? (*Interruptions*) That is up to the Government. I cannot ask them. If the Government wants to respond, he may do so. (*Interruptions*)

श्री बलबीर पुंज: क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे ...(व्यवधान) क्या आप तीर्थयात्रियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, केवल आतंकवादियों के लिए बोलेंगे ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Punj, you know the rules. It is up to the Government. (*Interruptions*)

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, when the matter related to terrorists was raised, the Government was very prompt to respond. (*Interruptions*) So much of inconvenience is being' caused to the *teerth yatris.* Government will have to... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have made your point. That is enough. (*Interruptions*) That is up to the Government. (*Interruptions*) Please take your seats. (*Interruptions*) That is up to the Government. (*Interruptions*) Please take your seat. You have made your point. That is enough. Please allow. ...(*Interruptions*).. आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)... Please allow. ...(*Interruptions*)... All of you sit down and one of you please say what do you want. ...(*Interruptions*)... All of you sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Punj, what do you want? ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, the Government has been very prompt in responding to the matter relating to two terrorists–one raised by Shri Tiwari and one raised by another hon. Member here. But in case of inconvenience to *teerth yatris* why is, the Government shy of taking steps? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have made your point. ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Does their heart bleed only for terrorists? ...(*Interruptions*)... Doesn't it bleed for *teerth yatris?* ...(*Interruptions*)...

श्री राम कृपाल यादव: आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Take your seat. ...(*Interruptions*)...

माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, माननीय मंत्री जी से कहिए कि ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is up to the, Government. ...(*Interruptions*)... I can't direct. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश): सर, ...(व्यवधान)... आप उनको कहिए कि ...(व्यवधान)...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, ...(व्यवधान)... इस यात्रा के प्रति क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नही है? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): If they want, they can reply. ...(*Interruptions*)... It is up to the Government. ...(*Interruptions*)... Would you like to respond? ...(*Interruptions*)...

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हरीश रावत): सर, माननीय सदस्यों की भावनाएं मैंने सुन ली हैं और उसके विषय में जो भी एप्रोप्रिएट कदम उठाने होंगे, जरूर उठाए जाएंगे। यह यात्रा एक

[श्री हरीश रावत]

परम्परागत यात्रा है। हम सब लोग इस यात्रा का सम्मान करते हैं। इसमें सब की भवनाएं हैं, कसी एक पक्ष या दो पक्ष की भावनाओं का सवाल नहीं है, जिस तरीके से इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। ...(व्यवधान)...

Reduction in Kerosene Quota of Andhra Pradesh

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Sir, this is regarding reduction in kerosene quota of Andhra Pradesh meant for BPL families.

Sir, kerosene is called 'poor man's fuel' and is used by the poor and the downtrodden for cooking and lightening. The successive Governments have rightly been providing kerosene to poor at subsidized rate. But, if you look at the supply of kerosene to Andhra Pradesh, it has been coming down almost every year.

Earlier, the Government used to supply 1 lakh kilolitres of kerosene to Andhra Pradesh and the State Government used to supply 15 litres for every BPL cardholder. But, in the name of Deepam connections, the Government of India reduced it by 25,000 kilolitres and again by 22,000 kilolitres. This resulted in reduction in quota from 15 litres to 4 litres for the poor living in cities and towns, only 2 litres for people in Mandals and only 1 litre for the poor in villages. As it is not enough, the Government yesterday further cut the quota of kerosene to Andhra Pradesh by 4,000 kilolitres and thereby reduced the quota to 38,800 kilolitres. On the one hand, the poor are demanding for increasing the quota and on the other Government is reducing it without assessing the ground realities. The UPA Government says that its Government is for *Aam Aadmi.* If it is for *Aam Aadmi* on what basis has it reduced the quota to Andhra Pradesh?

I strongly feel that it is a part of the Government's nefarious plan to ultimately stop supply of subsidized kerosene to poor in Andhra Pradesh. It is because Government is seriously thinking of transferring money directly to beneficiaries in the next one year with the objective of stopping kerosene diversion. So, I question: How is the decision to reduce kerosene by 4,000 kilolitres justified to poor? Secondly, by the time Government introduces money transfer to beneficiary, there would not be any supply of subsidized kerosene in Andhra Pradesh. So, this is a larger scheme of Government to deny benefit to the poor.

In view of the above, I demand for de-notifying the order meant to reduce 4,000 kilolitres from this month immediately and also request for restoration of original quota of 1 lakh kilolitres. Thank you.